HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1507/2021

Regional Manager, Iffco Tokio General Insurance Company Limited, Address- Third Floor A-13, And 37, Hanuman Nagar, Khatipura Tiraha, Sirsi Road, Jaipur, Presently At 2Nd Floor, Bhagwati Bhawan, Government Hostel Crossing M.i. Road, Jaiupr-302001, Rajasthan (Insurance Company Trailer No. Hr-55-N-8581)

----Appellant

Versus

1. Shrimati Sunita Devi W/o Late Shri Omprakash, aged 25 years,
2. Kumari Ameesha D/o Late Shri Omprakash, Aged About 2$_{1/2}$ years.,
3. Devraj S/o Late Shri Omprakash, Aged About 1 Years,
4. Manglaram S/o Shri Nanag, age 70 years (Died),
5. Prabhati W/o Manglaram, aged 65 years,

   all Resident Of Dhaani Seesatya, Tan Bajrangpura, Antela Police Station Shahpura, District Jaipur.

----Respondents/Claimants

6. Laxmi Narayan Jat S/o Shri Nanuram Jat, Resident Of 105, Sushant Lok, Gurgaon, Haryana. (Registered Vehicle Owner Trailer No. HR-55-N-8581)

----Respondent/Non-Applicant No.1

For Appellant(s)	:	Mr. Yashdeep Singh, Adv. Mr. Rajdeep Rathore, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

24/02/2026

अपीलार्थी–विपक्षी संख्या.–2/बीमा कंपनी (जिसे आगे विपक्षी संख्या–2 कहा जाएगा) की ओर से यह अपील विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जयपुर द्वारा प्रकरण E.C.C.F. 260/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2021 से व्यथित होकर पेश की है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/दावेदारों को उनके पिता/पति मृतक ओमप्रकाश की विपक्षी संख्या–1 के नियोजन के दौरान मृत्यु होने के आधार पर कुल **5,14,625/–**रूपये प्रतिकर 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 वस्तुतः औपचारिक पक्षकार है तथा मूल प्रकरण में दावेदार रहे हैं। प्रत्यर्थी संख्या 6 पर लंबे समय से नोटिस तामील नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसी प्रक्रम पर अपील की पोषणीयता के बिन्दु पर अपीलार्थी – विपक्षी संख्या–2 की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–बीमा कंपनी का निवेदन है कि मृतक प्रत्यर्थी संख्या 6 के यहां मृत्यु के समय कर्मकार के रूप में नियोजित हो, इस संबंध में अभिलेख पर कोई सामग्री व साक्ष्य नहीं है, अपीलाधीन निर्णय तथ्यों व विधि के विपरीत होकर मनमाना, अनुचित व दूषित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 के पैरा संख्या–9, 10, 11 तथा 12 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है–

9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

उपरोक्त न्यायिक निर्णय तथा अधिनियम–1923 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने पर ही अपील पोषणीय है।

वर्तमान मामले में प्रार्थीया द्वारा अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित किया है कि मृतक विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व के ट्रेलर नंबर एच.आर.–55–एन–8581 पर दुर्घटना के समय चालक था तथा जिस समय वह वाहन चला रहा था उस समय हार्ट अटैक के कारण से दौराने इलाज उसकी मृत्यु हुई। अपीलार्थी–बीमा कंपनी की ओर से खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

मृतक का विपक्षी संख्या–1 के यहां नियोजित होना, नियोजन के दौरान मृत्यु होना आदि सभी प्रश्न उपरोक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार तथ्यों से संबंधित है जिसके संबंध में सम्यक रूप से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष दिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह साक्ष्य के अभाव में हो अथवा उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री को नजर–अन्दाज किया गया हो अथवा जो तथ्य अभिलेख पर नहीं हो, उन पर विचार किया गया हो, ऐसी स्थिति नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है।

चूंकि विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अधिनियम–1923 की धारा–30 के प्रावधानों के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है, अतः यह अपील खारिज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2021 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

RAJASTHAN HIGH COURT

अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /43